कृषि आधारित रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

उत्तराखंड राज्य के हर विकासखण्ड में उभरेगा समृद्धि का मॉडल गांव

गांव की चौपाल से मोबाइल स्क्रीन तक

RNI No.: UPHIN/2018/76675
वर्ष 7 | अंक 6 | जून 2026 | ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका





छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर

छत्तीसगढ़



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- **5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना





इस अंक में







नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) : भारत के नए वैश्विक एविएशन युग का प्रवेश द्वार



भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार का नया कीर्तिमान



प्रशिक्षित युवा बन रहे समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई ताकत



डिजिटल क्रांति से बदली छोटे कारोबारों की तस्वीर

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

मूल्यः 20 रुपये, जून 2026

वर्ष-7 अंकः 6, पृष्ठः 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह

संपादक
अहमद हसन

सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com
E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com
Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड-	**विनय त्रिवाल**
उत्तर प्रदेश-	**लल्लन कुमार मिश्रा**
दिल्ली-	**दिनेश कुमार सिंह**
बिहार-	**सैयद मोहम्मद अली**
हरियाणा-	**संतोष कुमार सिंह**
झारखंड-	**परवेज कमाल**
डिजाइन-	**चंद्रजीत कुमार**

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार
NST MEDIA
WP-02, Block 'C'
Sector - 71, Noida - 201301
Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय

मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।

पत्र का नाम-
निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times)

RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

"रोजगार से आत्मनिर्भरता तक – नया भारत, नई उड़ान"

भारत आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहाँ विकास की परिभाषा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के जीवन में अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। "रोजगार से आत्मनिर्भरता तक" की यह यात्रा वास्तव में नए भारत की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

रोजगार किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होता है। जब रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो समाज में स्थिरता और समृद्धि आती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति और सरकारी योजनाओं ने रोजगार के नए आयाम खोले हैं। आज युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं रोजगार सृजनकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

आत्मनिर्भरता की अवधारणा ने देश के विकास मॉडल को नई दिशा दी है। इसका उद्देश्य केवल आयात पर निर्भरता कम करना नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पादन, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी उद्योगों तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई देने लगी है।

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और कृषि-उद्यमिता ने किसानों को केवल उत्पादक नहीं बल्कि व्यवसायी के रूप में भी स्थापित किया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" जैसी पहलों ने उत्पादन क्षमता और रोजगार दोनों को बढ़ाया है।

डिजिटल भारत ने भी रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खोले हैं। आज फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाएँ और स्टार्टअप्स युवाओं के लिए नए अवसरों का माध्यम बन चुके हैं। सरकार की कौशल विकास योजनाएँ इस परिवर्तन को और मजबूत कर रही हैं।

हालाँकि, इस यात्रा में चुनौतियाँ भी हैं—कौशल अंतराल, क्षेत्रीय असमानता और तकनीकी बदलाव के साथ तालमेल की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। इन चुनौतियों का समाधान शिक्षा, प्रशिक्षण और सतत नीति सुधारों से ही संभव है।

"नया भारत" केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर विकसित होती हुई प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। जब रोजगार आत्मनिर्भरता में बदलता है, तो राष्ट्र केवल विकसित ही नहीं होता, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान भी स्थापित करता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि भारत की यह नई उड़ान एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करती है जहाँ विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा।

"नया भारत" केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर विकसित होती हुई प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। जब रोजगार आत्मनिर्भरता में बदलता है, तो राष्ट्र केवल विकसित ही नहीं होता, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान भी स्थापित करता है।



मजबूत नींव पर खड़ी भारत की विकास गाथा

चुनौतियों के बीच भी उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर हाल ही में HDFC Bank Limited ने यह विश्वास जताया है कि वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारत की दीर्घकालिक (Long Term) ग्रोथ स्टोरी अत्यंत मजबूत बनी हुई है। यह दृष्टिकोण निवेशकों और नीति निर्माताओं दोनों के लिए सकारात्मक संकेत देता है।

बढ़ती महंगाई, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिरता और लचीलापन दिखाया है। मजबूत घरेलू मांग, युवा जनसंख्या और डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार देश की विकास यात्रा को नई गति दे रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता क्रेडिट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में तेजी और वित्तीय समावेशन की नीतियां भारत की आर्थिक बुनियाद को और मजबूत बना रही हैं। साथ ही, स्टार्टअप इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जा रही हैं।

एचडीएफसी का यह दृष्टिकोण इस बात को रेखांकित करता है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की विकास कहानी संरचनात्मक रूप से मजबूत है और आने वाले वर्षों में यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और सुदृढ़ करेगा। ■

एचडीएफसी का यह दृष्टिकोण इस बात को रेखांकित करता है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की विकास कहानी संरचनात्मक रूप से मजबूत है और आने वाले वर्षों में यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और सुदृढ़ करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे

विकास की रफ्तार से दौड़ता उत्तर भारत का भविष्य पथ



गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनकर उभर रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संतुलन और आधुनिक भारत की गतिशील विकास यात्रा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाली यह परियोजना राज्य की विकास गाथा को नई दिशा देने का कार्य कर रही है।

इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसकी विशाल कनेक्टिविटी है। यह मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक विस्तारित है, जिससे लगभग पूरे उत्तर प्रदेश को एक मजबूत सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल यात्रा का समय काफी कम होगा, बल्कि माल और सेवाओं की आवाजाही भी पहले से कहीं अधिक सुगम और तेज हो जाएगी।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह परियोजना औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खोल रही है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस और नए निवेश क्षेत्र विकसित होने की प्रबल संभावना है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छोटे-बड़े उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा। कृषि प्रधान क्षेत्रों में किसानों को भी अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि की उम्मीद है।

पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हरित पट्टियों (ग्रीन बेल्ट), वृक्षारोपण और ऊर्जा दक्ष निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे का एक और महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय विकास का संतुलन है। अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक विकसित रहा है, जबकि पूर्वी हिस्से को विकास की गति पकड़ने में समय लगा है। यह एक्सप्रेसवे इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी को केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कम करेगा। इससे समग्र विकास को नई ऊर्जा मिलेगी।

पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, रास्ते में आने वाले छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय पहचान मिलने का अवसर मिलेगा।

पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हरित पट्टियों (ग्रीन बेल्ट), वृक्षारोपण और ऊर्जा दक्ष निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर भारत के भविष्य का वह मार्ग है जो विकास, समृद्धि और अवसरों की नई परिभाषा गढ़ रहा है। यह आने वाले वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि भारत को एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के रूप में भी स्थापित करेगा। ■

"आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम **आयात पर सतर्कता और घरेलू निर्माण को बढ़ावा"**



पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में दिए गए स्वदेशी उत्पादन और आयात पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भारत की आर्थिक नीति में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल के रूप में देखे जा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र तेजी से उभर रहा है, और ऐसे में सरकार की यह रणनीति देश को मजबूत औद्योगिक आधार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

मंत्री गोयल का जोर इस बात पर है कि अनावश्यक आयात को नियंत्रित किया जाए और उन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए, जहां भारत पहले से ही क्षमता विकसित कर चुका है या तेजी से विकसित कर सकता है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि देश के छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से रोजगार सृजन के नए अवसर खुलते हैं। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके साथ ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों को भी वास्तविक गति मिलती है।

आयात पर निगरानी का उद्देश्य व्यापार को रोकना नहीं, बल्कि संतुलित और रणनीतिक बनाना है, जिससे आवश्यक तकनीक और संसाधनों का आयात हो, जबकि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए देश में ही उत्पादन क्षमता विकसित की जा सके। यह नीति दीर्घकाल में भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कुल मिलाकर, यह पहल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम है, जो देश को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। ■

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके साथ ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों को भी वास्तविक गति मिलती है।



"भारत–न्यूज़ीलैंड व्यापार समझौता छोटे बाज़ार से वैश्विक अवसरों तक एक रणनीतिक छलांग"

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच उभरता हुआ व्यापार समझौता केवल दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार संरचना में एक नई सोच का संकेत देता है। यह साझेदारी दर्शाती है कि कैसे अपेक्षाकृत छोटे बाज़ार भी बड़े आर्थिक अवसरों का केंद्र बन सकते हैं, यदि दृष्टिकोण दीर्घकालिक और नवाचार-उन्मुख हो।

India जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार और New Zealand जैसे उच्च गुणवत्ता आधारित उत्पादन व कृषि विशेषज्ञता वाले देश मिलकर एक संतुलित और पूरक व्यापार मॉडल विकसित कर सकते हैं। इससे न केवल वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा, बल्कि तकनीक, शिक्षा, डेयरी, कृषि नवाचार और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग मजबूत होगा।

यह व्यापार समझौता केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो दोनों देशों को पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाकर वैश्विक सहयोग की नई परिभाषा गढ़ सकता है।

इस समझौते का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि यह छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए नए अंतरराष्ट्रीय द्वार खोल सकता है। भारतीय उत्पादकों को न्यूज़ीलैंड के प्रीमियम बाजारों तक पहुंच मिलेगी, जबकि न्यूज़ीलैंड की उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और उत्पाद भारत के विविध उद्योगों को लाभ पहुंचाएंगे।

इसके अलावा, यह साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में ऐसा सहयोग आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह व्यापार समझौता केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो दोनों देशों को पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाकर वैश्विक सहयोग की नई परिभाषा गढ़ सकता है। ■

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर)
भारत के नए वैश्विक एविएशन युग का प्रवेश द्वार



Noida International Airport केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के आर्थिक, औद्योगिक और वैश्विक संपर्क को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाली एक ऐतिहासिक परियोजना है। इसे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को विश्व के प्रमुख एविएशन हब्स की सूची में स्थापित करने की क्षमता रखता है।

इस परियोजना का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसका रणनीतिक स्थान है। जेवर में स्थित यह एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे वैश्विक नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे न केवल यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए द्वार भी खुलेंगे।

आर्थिक दृष्टि से यह एयरपोर्ट लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। निर्माण चरण से लेकर संचालन तक, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। यह क्षेत्र के युवाओं के लिए नए करियर अवसरों का केंद्र बनेगा।

आर्थिक दृष्टि से यह एयरपोर्ट लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। निर्माण चरण से लेकर संचालन तक, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। यह क्षेत्र के युवाओं के लिए नए करियर अवसरों का केंद्र बनेगा।

एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका "एयरोसिटी डेवलपमेंट मॉडल" है, जिसके तहत एयरपोर्ट के आसपास आधुनिक शहर, होटल, बिजनेस पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे। यह मॉडल न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि वैश्विक निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। विदेशी कंपनियों के लिए यह क्षेत्र एक नए निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी इस एयरपोर्ट को आधुनिक और सस्टेनेबल तकनीकों के साथ विकसित किया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसे भविष्य के "इको-फ्रेंडली एयरपोर्ट्स" की श्रेणी में शामिल करते हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव अत्यंत सकारात्मक होगा। आगरा, मथुरा, वृंदावन और लखनऊ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच अधिक सुगम हो जाएगी, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि होगी।

निष्कर्षतः, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि "नए भारत" की प्रगति, वैश्विक जुड़ाव और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह न केवल उत्तर भारत, बल्कि पूरे देश की विकास गाथा को एक नई दिशा देगा। ■

भव्य भारत की औद्योगिक उड़ान

100 इंडस्ट्रियल पार्कों से बदलेगी विकास की तस्वीर



'भव्य' योजना भारत के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर सकेगा। यह योजना न केवल निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी।

भारत सरकार ने देश को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'भव्य' (BHAVYA — भारत औद्योगिक विकास योजना) योजना की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देशभर में 100 आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह पहल भारत में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति देगी

₹33,660 करोड़ की विशाल योजना

सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 33,660 करोड़ का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य ऐसे "प्लग-एंड-प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित करना है, जहां उद्योगों को पहले से तैयार आधारभूत सुविधाएं मिल सकें और वे शीघ्र उत्पादन शुरू कर सकें। इन पार्कों का विकास केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी में किया जाएगा।

उद्योगों को मिलेगा तैयार वातावरण

भव्य योजना के तहत बनने वाले औद्योगिक पार्कों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति, भूमिगत पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम, वेयरहाउस, परीक्षण प्रयोगशालाएं, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट तथा श्रमिक आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे उद्योगों को अलग-अलग अनुमति और निर्माण में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।

सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ तक की सहायता आंतरिक अवसंरचना विकास के लिए देगी। वहीं निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी वाले प्रोजेक्ट्स को 50 लाख प्रति एकड़ तक सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्यों के बीच बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहले चरण में 20 पार्क, उसके बाद 30 और फिर शेष 50 पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में बेहतर भूमि, बिजली, पानी और उद्योग-अनुकूल नीतियां होंगी, वहां निवेश की संभावनाएं अधिक होंगी।

राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने पहले ही इस योजना में रुचि दिखाई है।

छोटे और पर्वतीय राज्यों को भी लाभ

जहां सामान्य औद्योगिक पार्क 100 से 1000 एकड़ तक होंगे, वहीं पर्वतीय राज्यों के लिए 25 एकड़ भूमि पर भी पार्क विकसित किए जा सकेंगे। इससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

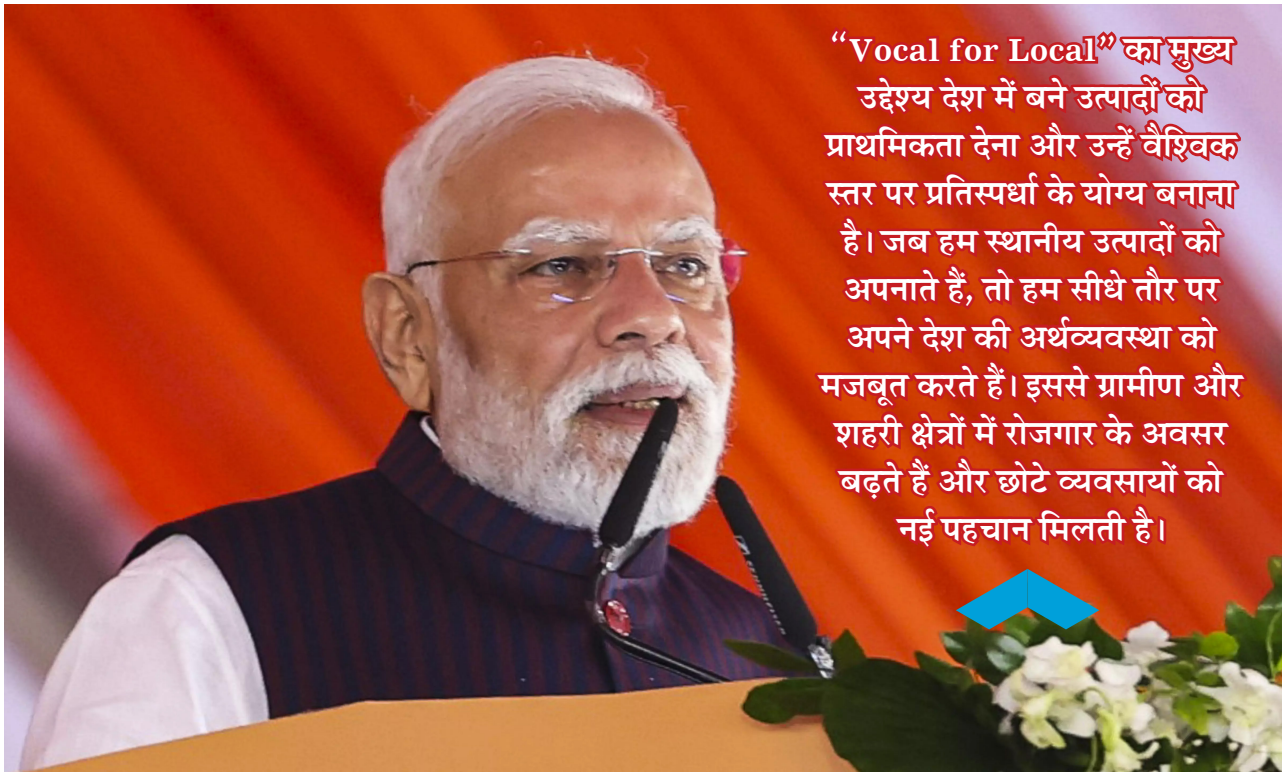
पीएम गतिशक्ति से जुड़ेगा विकास

भव्य योजना को National Industrial Corridor Development Corporation तथा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर लॉजिस्टिक्स और तेज़ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। औद्योगिक पार्कों में हरित ऊर्जा और सतत संसाधन उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रोजगार और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना केवल औद्योगिक पार्क बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में रोजगार सृजन, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और "मेक इन इंडिया" अभियान को नई ऊर्जा देने का माध्यम बनेगी। उद्योगों के क्लस्टर आधारित विकास से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। ■

VOCAL for LOCAL
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक पहल



आज के वैश्विक दौर में जब बाजार विदेशी उत्पादों से भरा हुआ है, ऐसे समय में "Vocal for Local" अभियान आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत और सकारात्मक कदम बनकर उभरा है। यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देती है, बल्कि देश के छोटे उद्योगों, कारीगरों और उद्यमियों के लिए नए अवसर भी पैदा करती है।

"Vocal for Local" का मुख्य उद्देश्य देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। जब हम स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं, तो हम सीधे तौर पर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और छोटे व्यवसायों को नई पहचान मिलती है।

भारत की परंपरागत कला, हस्तशिल्प, खादी, आयुर्वेदिक उत्पाद और घरेलू उद्योग इस अभियान से नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। आज अनेक युवा उद्यमी "लोकल से ग्लोबल" की सोच के साथ अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे देश में नवाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा, यह पहल पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि स्थानीय उत्पादों के उपयोग से परिवहन और आयात पर निर्भरता कम होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटता है। यह टिकाऊ विकास (Sustainable Development) की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

"Vocal for Local" केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो हमें अपने देश की क्षमता पर विश्वास करना सिखाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि यदि हम अपने ही देश के उत्पादों को अपनाएंगे, तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि "Vocal for Local" अभियान भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास है, जो आने वाले समय में देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। ■



झारखंड में औद्योगिक विकास की नई उड़ान

निवेश और सहयोग की दिशा में मजबूत कदम

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) झारखंड के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात राज्य के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल साबित हुई। यह बैठक कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें राज्य में निवेश, औद्योगिक नीतियों और विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल में CII झारखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष श्री दिलू पारिख, टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष श्री डी.बी. सुंदर रमन, CII ईस्टर्न रीजन के रीजनल डायरेक्टर श्री देव ज्योति तथा CII झारखंड हेड श्री प्रभात कुमार शामिल रहे। बैठक के दौरान उद्योग जगत और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड आज निवेश के लिए एक अनुकूल और संभावनाओं से भरपूर



मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड आज निवेश के लिए एक अनुकूल और संभावनाओं से भरपूर राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निरंतर नई और प्रभावी कार्ययोजनाओं पर काम कर रही है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की सक्रिय भागीदारी को उन्होंने राज्य की वैश्विक पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।



राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निरंतर नई और प्रभावी कार्ययोजनाओं पर काम कर रही है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की सक्रिय भागीदारी को उन्होंने राज्य की वैश्विक पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

CII प्रतिनिधियों ने भी झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य को एक उभरते निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने औद्योगिक नीति निर्माण में ज्ञान और उद्योग भागीदार के रूप में सहयोग देने की इच्छा जताई, जिससे नीतियों को और अधिक व्यावहारिक और निवेश-अनुकूल बनाया जा सके।

यह बैठक न केवल सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत साझेदारी का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि झारखंड आने वाले समय में औद्योगिक विकास और निवेश के नए आयाम स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। ■

कृषि आधारित रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था : विकास की नई दिशा

भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की जीवनरेखा कृषि है। आज कृषि केवल अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह रोजगार, उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रमुख माध्यम बन चुकी है। बदलती तकनीक, सरकारी योजनाओं और युवाओं की भागीदारी ने कृषि क्षेत्र को नए अवसरों से जोड़ दिया है।

कृषि आधारित रोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त साधन बन रहा है। खेती के साथ डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, मशरूम उत्पादन और जैविक खेती जैसे कार्य तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में कम लागत में अच्छा लाभ मिलने से गांवों में रोजगार के नए द्वार खुले हैं। विशेष रूप से महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, अचार, पापड़ और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम किसानों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ रही हैं। डिजिटल तकनीक के उपयोग से किसान अब बाजार भाव, मौसम जानकारी और नई कृषि तकनीकों तक आसानी से पहुंच बना रहे हैं। इससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कृषि आधारित उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों में स्थापित लघु उद्योग और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इससे पलायन में कमी आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

आज आवश्यकता है कि युवाओं को कृषि को केवल परंपरागत पेशा नहीं, बल्कि आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि कृषि और ग्रामीण उद्योगों को तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से निरंतर जोड़ा जाए, तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

कृषि आधारित रोजगार न केवल ग्रामीण जीवन को समृद्ध बना रहा है, बल्कि भारत के सतत और समावेशी विकास की मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है। ■



कौशल विकास मिशन

आत्मनिर्भर भारत की ओर युवाओं का सशक्त कदम









कौशल विकास मिशन युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए युवाओं को नई पहचान, नया आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर रहा है।

भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है, जो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे में युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि रोजगारपरक कौशल प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौशल विकास मिशन युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यह मिशन न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बना रहा है।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। उद्योगों और कंपनियों की मांग के अनुसार तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हो गया है। कौशल विकास मिशन युवाओं को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, कृषि, फैशन डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इससे युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने का अवसर मिल रहा है।

इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को भी आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। छोटे गांवों और कस्बों में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक तकनीकों से जोड़ रहे हैं। इससे बेरोजगारी कम होने के साथ-साथ पलायन की समस्या में भी कमी आ रही है। महिलाओं के सशक्तीकरण में भी कौशल विकास मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिलाई, ब्यूटी एवं वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण और ऑनलाइन व्यवसाय जैसे कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब महिलाएं घर बैठे स्वरोजगार शुरू कर परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप संस्कृति के इस युग में कौशल विकास मिशन युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। प्रशिक्षित युवा आज छोटे-छोटे स्टार्टअप शुरू कर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

कौशल विकास मिशन युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए युवाओं को नई पहचान, नया आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर रहा है। यदि युवा अपनी प्रतिभा को सही दिशा में विकसित करें, तो भारत विश्व में कौशल और नवाचार की महाशक्ति बन सकता है। ■

शिक्षा से रोजगार तक

आत्मनिर्भर भारत की मजबूत होती नई कड़ी

आज के दौर में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह रोजगार और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी साधन बन चुकी है। बदलती तकनीक, उद्योगों की नई मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा तथा रोजगार के बीच की दूरी को कम किया है। यही कारण है कि आज की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल भी प्रदान कर रही है।





नई शिक्षा नीति, कौशल विकास कार्यक्रम और डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। अब विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा, संचार कौशल तथा उद्यमिता की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे नौकरी पाने के साथ-साथ स्वयं रोजगार सृजित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे "स्किल इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसे अभियान शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

आज कंपनियां भी ऐसे युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान और समस्या समाधान की क्षमता हो। इसी कारण इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही कार्य अनुभव प्राप्त हो जाता है, जो उनके भविष्य को मजबूत बनाता है।

शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती यह कड़ी देश के आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत सकारात्मक संकेत है। जब युवा शिक्षित और कुशल होंगे, तब वे राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी योगदान दे पाएंगे। स्पष्ट है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि अवसर पैदा करने वाला नागरिक बना रही है। ■

शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती यह कड़ी देश के आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत सकारात्मक संकेत है। जब युवा शिक्षित और कुशल होंगे, तब वे राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी योगदान दे पाएंगे।



औद्योगिक विकास : नए भारत के रोजगार का स्वर्णिम दौर

भारत आज तेजी से औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल क्रांति और सरकारी योजनाओं के कारण देश में नए उद्योगों का विस्तार हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को नए रोजगार क्षेत्रों के रूप में मिल रहा है। यह परिवर्तन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है।

वर्तमान समय में ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और ई–कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो रहा है। "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसी योजनाओं ने उद्योगों को नई गति प्रदान की है। विदेशी कंपनियाँ भी भारत में निवेश कर रही हैं, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है।

औद्योगिक विकास का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि अब रोजगार के पारंपरिक तरीकों में बदलाव आया है। पहले लोग केवल सरकारी नौकरी को ही सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब निजी क्षेत्र और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। आज एक युवा तकनीकी ज्ञान और रचनात्मक सोच के आधार पर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकता है और दूसरों को भी रोजगार दे सकता है।

कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी है। यदि इसी प्रकार उद्योगों और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता रहा, तो भारत विश्व में रोजगार और नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

ग्रीन एनर्जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में रोजगार अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल सेवाओं से जुड़े उद्योग भविष्य के मजबूत रोजगार क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को भी बल मिल रहा है।

कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी है। यदि इसी प्रकार उद्योगों और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता रहा, तो भारत विश्व में रोजगार और नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। ■



भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार का नया कीर्तिमान

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2026 की पहली तिमाही एक अत्यंत सकारात्मक संकेत लेकर आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी Quarterly Bulletin of Unincorporated Sector Enterprises (QBUSE) के अनुसार, देश के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार पहली बार 15 करोड़ (150 मिलियन) के पार पहुँच गया है। जनवरी-मार्च 2026 के दौरान इस क्षेत्र में कुल रोजगार 15.51 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 151.7 मिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 131.3 मिलियन था।

यह उपलब्धि केवल रोजगार बढ़ने का आँकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था में बढ़ती सक्रियता, उद्यमशीलता और ग्रामीण विकास की मजबूत तस्वीर प्रस्तुत करती है।

ग्रामीण भारत बना विकास का इंजन

रिपोर्ट का सबसे उत्साहजनक पक्ष यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेज़ वृद्धि दर्ज की। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 10.39 प्रतिशत रही। इसी प्रकार ग्रामीण प्रतिष्ठानों (establishments) की संख्या में 20.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

यह दर्शाता है कि गाँवों में छोटे व्यापार, सेवा गतिविधियाँ और स्वरोज़गार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।

सेवा क्षेत्र बना सबसे बड़ा सहारा

असंगठित क्षेत्र में सेवा क्षेत्र (Services Sector) सबसे तेज़ी से उभरकर सामने आया है। सेवा प्रतिष्ठानों की संख्या में 24.82 प्रतिशत और रोजगार में 31.13 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि देश में स्थानीय सेवाओं—जैसे मरम्मत कार्य, परिवहन, डिजिटल सेवाएँ, घरेलू सेवाएँ, छोटे व्यवसाय और अन्य स्वरोज़गार गतिविधियों—की माँग लगातार बढ़ रही है। साथ ही, लोगों में उद्यमिता की भावना भी मजबूत हो रही है।

डिजिटल और औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता कदम

रिपोर्ट में यह तथ्य भी बेहद सकारात्मक है कि लगभग 81 प्रतिशत प्रतिष्ठान इंटरनेट का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए कर रहे हैं और लगभग इतने ही प्रतिष्ठानों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाई है।

UPI, ऑनलाइन बैंकिंग और POS मशीनों का बढ़ता उपयोग यह दिखाता है कि देश का छोटा व्यवसाय वर्ग भी डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यापार आसान होगा और आर्थिक गतिविधियाँ अधिक संगठित बनेंगी।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 29 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। यह महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। आज महिलाएँ छोटे व्यापार, घरेलू उद्योग, सेवा कार्यों और स्वरोज़गार के माध्यम से आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

भारत का असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। रोजगार, उद्यमिता, ग्रामीण विकास, डिजिटल अपनाने और महिला भागीदारी में हुई यह प्रगति बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। यदि यही गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देगा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ■



स्टार्टअप संस्कृति और युवा उद्यमिता : नए भारत की उभरती ताकत

आज का युवा केवल नौकरी पाने का सपना नहीं देखता, बल्कि रोजगार देने की सोच भी विकसित कर रहा है। यही सोच भारत में तेजी से बढ़ती स्टार्टअप संस्कृति को नई दिशा दे रही है। तकनीक, नवाचार और आत्मविश्वास के बल पर युवा उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्टार्टअप संस्कृति का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि यह युवाओं को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता को पहचानने का अवसर देती है। पहले व्यवसाय शुरू करना केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हर युवा के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अब अपने विचारों को व्यवसाय का रूप देकर सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

युवा उद्यमिता रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। एक सफल स्टार्टअप केवल उसके संस्थापक को ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार देता है। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। इसके साथ ही स्टार्टअप संस्कृति आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूत बनाती है।

स्टार्टअप युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और समस्या समाधान की भावना विकसित करते हैं। असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना उद्यमिता का महत्वपूर्ण गुण है, जो युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनाता है। आज कई युवा पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

स्टार्टअप संस्कृति और युवा उद्यमिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि नए भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और नवाचार की पहचान बन चुकी है। युवा शक्ति यदि इसी प्रकार आगे बढ़ती रही, तो भारत विश्व में उद्यमिता का प्रेरणास्रोत बन सकता है।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे "स्टार्टअप इंडिया" और "मेक इन इंडिया" जैसे अभियान भी युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। निवेश, प्रशिक्षण और डिजिटल सुविधाओं के कारण भारत विश्व का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनता जा रहा है।

स्टार्टअप संस्कृति और युवा उद्यमिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि नए भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और नवाचार की पहचान बन चुकी है। युवा शक्ति यदि इसी प्रकार आगे बढ़ती रही, तो भारत विश्व में उद्यमिता का प्रेरणास्रोत बन सकता है। ■



भारत की आर्थिक रीढ़
MSME की बढ़ती ताकत और उज्ज्वल भविष्य

भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र केवल उत्पादन और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के रोजगार, आत्मनिर्भरता और नवाचार का मजबूत आधार भी बन चुका है। आज MSME देश की आर्थिक रीढ़ के रूप में उभर रहा है और "आत्मनिर्भर भारत" के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

MSME क्षेत्र ग्रामीण और शहरी भारत के बीच आर्थिक संतुलन स्थापित करने में सहायक है। छोटे स्तर पर शुरू होने वाले उद्योग कम पूंजी में अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, डिजिटल सेवाएँ और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से यह क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रहा है।

सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से MSME क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। आसान ऋण सुविधा, तकनीकी सहायता और ऑनलाइन बाजार तक पहुँच ने छोटे उद्योगों की कार्यक्षमता को बढ़ाया है। कोविड-19 जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी MSME ने अपनी दृढ़ता और लचीलापन साबित किया तथा देश की सप्लाई चेन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। ■

सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से MSME क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। आसान ऋण सुविधा, तकनीकी सहायता और ऑनलाइन बाजार तक पहुँच ने छोटे उद्योगों की कार्यक्षमता को बढ़ाया है।

गांव की चौपाल से मोबाइल स्क्रीन तक
दुग्ध क्रांति की नई तस्वीर



उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया तकनीक आधारित दुग्ध नेटवर्क अब गांवों की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है। 'सामर्थ्य दुग्ध उत्पादक कंपनी' के माध्यम से अवध क्षेत्र और आसपास के 10 जिलों की महिलाएं अब मोबाइल एप और डिजिटल तकनीक के जरिए दुग्ध व्यापार का संचालन कर रही हैं। यह पहल केवल दूध खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सशक्तीकरण का सशक्त उदाहरण बन चुकी है।

लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, प्रतापगढ़, कानपुर नगर और फतेहपुर जैसे जिलों में गांव-गांव दुग्ध संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का संचालन स्वयं ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। इससे एक ओर महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है, वहीं दूसरी ओर पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य सुनिश्चित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका को लगभग समाप्त कर दिया है।

आज इस नेटवर्क से सवा लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ चुकी हैं और प्रतिदिन चार लाख लीटर से ज्यादा दूध का कारोबार डिजिटल माध्यम से संचालित हो रहा है। यह आंकड़ा केवल आर्थिक गतिविधि का प्रतीक नहीं, बल्कि गांवों में बढ़ते महिला नेतृत्व और तकनीकी भागीदारी का प्रमाण भी है।

निश्चित रूप से यह पहल उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। गांव की चौपाल से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंची यह दुग्ध क्रांति आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल साबित हो सकती है।

इस पहल का सबसे आधुनिक और प्रभावशाली पक्ष है 'सामर्थ्य साथी' मोबाइल एप। यह एप दुग्ध उत्पादकों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। दूध की मात्रा, गुणवत्ता जांच, भुगतान की स्थिति और बिक्री से जुड़ी सभी सूचनाएं अब मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं में पारदर्शिता के प्रति विश्वास बढ़ा है और उन्हें अपने कार्य पर अधिक नियंत्रण मिला है।

सरकार द्वारा भुगतान व्यवस्था को भी पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। महिला दुग्ध उत्पादकों को महीने में तीन बार, हर दस दिन के अंतराल पर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। इससे आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था के प्रति महिलाओं की जागरूकता भी बढ़ी है। अब ग्रामीण महिलाएं केवल पशुपालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड, डेटा प्रबंधन और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को भी आत्मविश्वास के साथ संभाल रही हैं।

इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल प्रशिक्षण भी है। गांव स्तर पर महिलाओं को तकनीकी जानकारी दी जा रही है ताकि वे मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर सकें। यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं को नई तकनीक से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहा है।

यह मॉडल ग्रामीण विकास की उस नई सोच को दर्शाता है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रमुख भागीदार बन रही हैं। दुग्ध उत्पादन जैसे पारंपरिक क्षेत्र में तकनीक का समावेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्वरूप दे रहा है। इससे गांवों में आत्मनिर्भरता, रोजगार और सामाजिक सम्मान तीनों को मजबूती मिल रही है।

निश्चित रूप से यह पहल उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। गांव की चौपाल से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंची यह दुग्ध क्रांति आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल साबित हो सकती है। ■



खेत तालाब योजना जल संरक्षण से समृद्धि की ओर बढ़ते किसान

उत्तर प्रदेश में कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित 'खेत तालाब योजना' आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रही है। यह योजना केवल सिंचाई सुविधा तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों के लिए अतिरिक्त आय और बहुआयामी कृषि विकास का मजबूत आधार बनती जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संचयन कर किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। लगातार गिरते भूगर्भ जल स्तर और अनिश्चित मौसम की चुनौतियों के बीच खेत तालाब किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। खेतों में तैयार किए जा रहे तालाब वर्षा के पानी को सुरक्षित रखते हैं, जिससे सूखे या कम बारिश की स्थिति में भी फसलों की सिंचाई निर्बाध रूप से हो पा रही है।

योजना के तहत 22×20×3 मीटर आकार के तालाब के निर्माण पर कुल 1,05,000 की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार 52,500 तक का अनुदान प्रदान कर रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी इस योजना से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। सरकार की यह सहायता ग्रामीण किसानों के आर्थिक बोझ को कम करते हुए उन्हें आधुनिक कृषि की ओर प्रेरित कर रही है।

'खेत तालाब योजना' किसानों के लिए अतिरिक्त आय के नए द्वार भी खोल रही है। तालाबों में मत्स्य पालन, मोती उत्पादन, सिंघाड़ा खेती और अन्य जलीय कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसान खेती के साथ-साथ वैकल्पिक आय अर्जित कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और किसान आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश सरकार आधुनिक सिंचाई तकनीकों



योजना का लाभ लेकर खेत तालाब से किसान कर रहे मत्स्य पालन, मोती, सिंघाड़ा एवं अन्य जलीय खेती



को भी बढ़ावा दे रही है। स्प्रिंकलर सेट पर 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान तथा पम्पसेट पर 15,000 या 50 प्रतिशत तक सहायता किसानों को दी जा रही है। इससे जल संरक्षण के साथ सिंचाई लागत में भी कमी आ रही है।

योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था है। किसानों का चयन ऑनलाइन पोर्टल पर "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के आधार पर किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और सिफारिश की संभावना समाप्त हो रही है। ऑनलाइन आवेदन, समयबद्ध सत्यापन और चरणबद्ध अनुदान प्रक्रिया किसानों को सरल और सुगम सुविधा प्रदान कर रही है।

'खेत तालाब योजना' किसानों के लिए अतिरिक्त आय के नए द्वार भी खोल रही है। तालाबों में मत्स्य पालन, मोती उत्पादन, सिंघाड़ा खेती और अन्य जलीय कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसान खेती के साथ-साथ वैकल्पिक आय अर्जित कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और किसान आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भूमि संरक्षण अधिकारी आर.पी. कुशवाहा के अनुसार, यह योजना खेती को सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। खेत तालाब बनने से किसानों की मौसम पर निर्भरता कम हो रही है और फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है।

'खेत तालाब योजना' उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण, आधुनिक कृषि और ग्रामीण समृद्धि का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है, जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ■

उत्तर प्रदेश: रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता का उभरता राष्ट्रीय मॉडल

नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले युवा— यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने रोजगार, निवेश, उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखा है, वह केवल सरकारी उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक बड़ी कहानी बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की ऐसी नई दिशा पकड़ी है, जिसमें युवा और महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास के भागीदार बनकर उभरे हैं।

आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाता राज्यों में गिना जा रहा है। पहले जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता था, वहीं अब वही युवा अपने राज्य में अवसर तलाश रहे हैं और कई युवा स्वयं उद्यम स्थापित कर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। यह बदलाव योजनाबद्ध नीति, निवेश को बढ़ावा और पारदर्शी प्रशासन





का परिणाम माना जा रहा है।

सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते नौ वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। पुलिस विभाग में 2.19 लाख से अधिक भर्तियां पूरी की गईं, जबकि शिक्षा विभाग में 1.65 लाख से ज्यादा नियुक्तियां हुईं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2026 में 80 हजार से अधिक नई भर्तियों की तैयारी यह दर्शाती है कि सरकार रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सफलता केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रही। प्रदेश ने स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाई है। एमएसएमई सेक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। वर्ष 2017 से पहले जहां प्रदेश में लगभग 14 हजार कारखाने पंजीकृत थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 31 हजार से अधिक हो चुकी है। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। केवल एमएसएमई क्षेत्र से ही तीन करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।

सरकार की योजनाओं ने युवाओं में उद्यमिता



रोजगार, निवेश, उद्योग, महिला सशक्तीकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश को रोजगार और आत्मनिर्भरता के सबसे सफल मॉडलों में गिना जा रहा है।

की भावना को भी मजबूत किया है। "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" जैसी योजनाओं ने शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को उद्योग स्थापित करने का अवसर दिया। वर्ष 2024-25 से अब तक 1.47 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिला, जिससे लगभग 4.51 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने। यह दर्शाता है कि प्रदेश में अब युवा नौकरी पाने के साथ-साथ नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं।

निवेश के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले नौ वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे एक करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए, जिनसे 60 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित हुए। यह उपलब्धि बताती है कि उत्तर प्रदेश अब उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने प्रभावशाली कदम उठाए हैं। बीसी सखी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया। महिलाओं ने बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में 42,711 करोड़ रुपये का लेन-देन कर अपनी आर्थिक क्षमता का परिचय दिया और 116 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया। स्वयं सहायता समूहों और "लखपति दीदी" अभियान ने ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज प्रदेश की 18.55 लाख महिलाएं लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं और एक करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर रही हैं।

खेती और तकनीक के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और महिला आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है।

खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी सेवाओं में अवसर देकर सरकार ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जा चुकी है। यह नीति युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रोजगार सुरक्षा भी प्रदान कर रही है।

आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। प्रदेश का युवा अब अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करता,

बल्कि नए स्टार्टअप, उद्योग और व्यवसाय के जरिए अपनी पहचान बना रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक आत्मनिर्भरता की नई लहर दिखाई दे रही है।

रोजगार, निवेश, उद्योग, महिला सशक्तीकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश को रोजगार और आत्मनिर्भरता के सबसे सफल मॉडलों में गिना जा रहा है। ■

उभरता भारत का नया मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब

उत्तर प्रदेश आज केवल देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक और सप्लाई चेन शक्ति के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकसित हो रहा विशाल मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उद्योग, व्यापार और निवेश की तस्वीर बदल रहा है। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्क अब प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ने का मजबूत माध्यम बन चुके हैं।

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति लंबे समय तक केवल एक "लैंडलॉक स्टेट" के रूप में देखी जाती थी, लेकिन अब यही स्थिति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक मार्ग प्रदेश के हर क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और औद्योगिक शहरों से सीधे जोड़ रहे हैं। इससे माल परिवहन की गति बढ़ी है, लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है और उद्योगों को बेहतर सप्लाई चेन नेटवर्क प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने और अधिक मजबूती दी है। पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का संगम प्रदेश को देश के सबसे बड़े माल परिवहन केंद्रों में बदल रहा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में विकसित हो रहा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब उत्तर भारत के सबसे बड़े कार्गो और कंटेनर नेटवर्क का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही कानपुर, गोरखपुर और टप्पल-बजना जैसे क्षेत्रों में विकसित हो रहे नए लॉजिस्टिक्स पार्क औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा दे रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के किनारे विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को और विस्तार देंगे। मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित इन क्लस्टर्स से वेयरहाउसिंग,





उत्तर प्रदेश को लीड्स 2025 रिपोर्ट में "एग्जम्पलर" श्रेणी में स्थान मिलना इस परिवर्तन का बड़ा प्रमाण है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इकोसिस्टम को नई मजबूती मिलेगी। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

प्रदेश में एग्री-लॉजिस्टिक्स सेक्टर का विस्तार भी उल्लेखनीय है। आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, मल्टी-कमोडिटी कूलिंग सेंटर और कृषि उत्पादों के लिए उन्नत स्टोरेज सुविधाएं किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रही हैं। फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद अब तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिल रही है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा Noida International Airport भी प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला साबित हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे बड़े एविएशन और कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी एक विश्वस्तरीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जो निर्यात आधारित उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

वाराणसी मल्टीमॉडल टर्मिनल और इनलैंड वाटरवे परियोजनाएं भी प्रदेश को कम लागत वाले नदी आधारित कार्गो परिवहन से जोड़ रही हैं। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और मल्टीमॉडल फ्रेट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

डिजिटल गवर्नेंस और निवेश सुधारों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। 'निवेश मित्र' जैसे सिंगल विंडो सिस्टम तथा जीआईएस आधारित डिजिटल प्लानिंग टूल्स ने निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। यही कारण है कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में तेजी से आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश को लीड्स 2025 रिपोर्ट में "एग्जम्पलर" श्रेणी में स्थान मिलना इस परिवर्तन का बड़ा प्रमाण है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ■



प्रशिक्षित युवा बन रहे **समृद्ध उत्तर प्रदेश** की नई ताकत

उत्तर प्रदेश आज केवल देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि सबसे बड़ी युवा शक्ति का केंद्र भी बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पिछले नौ वर्षों में युवाओं को कौशल, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिस व्यापक स्तर पर कार्य किया है, उसने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें प्रदेश की आर्थिक प्रगति का सहभागी बनाना है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने कौशल विकास को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ा। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑटोमोबाइल, निर्माण, फैशन डिजाइनिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कृषि आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पिछले नौ वर्षों में लगभग 14 लाख युवाओं को विभिन्न विधाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 7.50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग भी मजबूत हुआ।

आज उत्तर प्रदेश "स्किल कैपिटल" के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार के समन्वय से प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी "प्रोजेक्ट प्रवीण" योजना इस दिशा में विशेष रूप से प्रभावी साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.35 लाख विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक दक्षता प्रदान करना है, ताकि वे डिग्री प्राप्त करने के साथ रोजगार के लिए भी पूरी तरह तैयार रहें। इससे शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन भी किया। पिछले नौ वर्षों में आयोजित 188 वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 4.40 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इन मेलों में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों और निजी क्षेत्र के संस्थानों ने भाग लिया, जिससे युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर रोजगार मिला और पलायन में भी कमी आई। सरकार युवाओं को नौकरी तक सीमित न रखकर उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और मार्केट लिंकिंग उपलब्ध कराई जा रही है। परिणामस्वरूप प्रदेश में स्टार्टअप, एमएसएमई और स्थानीय उद्योगों से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश "स्किल कैपिटल" के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार के समन्वय से प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योगी सरकार की यह पहल न केवल युवाओं के भविष्य को सशक्त बना रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में भी मजबूत आधार तैयार कर रही है। ■

ऑपरेशन-4' से बदलता उत्तर प्रदेश : स्वदेशी गायों के सहारे समृद्ध गांवों की नई तस्वीर



उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डेयरी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। स्वदेशी गायों के संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई चार महत्वाकांक्षी योजनाओं ने गांवों में नई उम्मीद जगाई है। यही वजह है कि इसे अब 'ऑपरेशन-4' के रूप में देखा जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से दो गायों से लेकर 25 गायों तक की डेयरी इकाइयों पर लाखों रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसान भी डेयरी व्यवसाय से जुड़ पा रहे हैं।

सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें जमीन पर तेजी से उतारा गया है। डेयरी स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, 35 प्रतिशत बैंक ऋण और केवल 15 प्रतिशत लाभार्थी निवेश का मॉडल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना के तहत दो गायों की इकाई पर 80 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाना पशुपालकों के लिए बड़ी राहत है।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण का एक व्यापक अभियान बन चुकी है। 'ऑपरेशन-4' आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे मजबूत डेयरी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।



प्रदेश सरकार का विशेष फोकस गिर, साहीवाल, गंगातीरी और सिंधी जैसी उन्नत स्वदेशी नस्लों पर है। ये नस्लें अधिक दूध उत्पादन के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य और अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती हैं। इनके संरक्षण से न केवल भारतीय नस्लों की पहचान मजबूत होगी, बल्कि डेयरी उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी।

इन योजनाओं का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि गांवों में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाएं और युवा डेयरी व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इससे पलायन कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पशुपालन विभाग के अनुसार प्रदेश में हजारों डेयरी इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की जा चुकी है।

योगी सरकार की यह पहल केवल डेयरी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण का एक व्यापक अभियान बन चुकी है। 'ऑपरेशन-4' आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे मजबूत डेयरी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ■



एक जनपद एक व्यंजन

उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुँचाने की ऐतिहासिक पहल

उत्तर प्रदेश सरकार की "एक जनपद एक व्यंजन" (ODOP/ODOC) योजना राज्य की समृद्ध पाक परंपरा को नई पहचान और वैश्विक विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम के रूप में उभर रही है। यह पहल केवल खानपान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे संस्कृति, रोजगार, उद्यमिता और निर्यात से जोड़कर एक समग्र विकास मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों की पहचान कर उन्हें वैज्ञानिक, संगठित और मानकीकृत रूप दिया जाएगा। इसके लिए FSSAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से "स्टैंडर्ड रेसिपी मैन्युअल" तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हर व्यंजन का स्वाद, गुणवत्ता और पोषण मूल्य एक समान बना रहे। यह पहल न केवल पारंपरिक स्वाद को संरक्षित करेगी, बल्कि उसे आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाएगी।

"एक जनपद एक व्यंजन" योजना न केवल उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्वाद को संरक्षित कर रही है, बल्कि उसे आधुनिक तकनीक, बाजार और वैश्विक अवसरों से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति की नींव रख रही है।

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू स्मार्ट और आधुनिक पैकेजिंग है। इको-फ्रेंडली पैक, क्यूआर कोड, बारकोड और न्यूट्रीशन लेबलिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश के स्थानीय व्यंजन राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

इसके साथ ही स्थानीय उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सरकार सक्रिय है। पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

"स्वाद यूपी का" जैसी ब्रांडिंग पहल और डिजिटल प्रचार अभियानों के माध्यम से इन व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। यह प्रयास उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

"एक जनपद एक व्यंजन" योजना न केवल उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्वाद को संरक्षित कर रही है, बल्कि उसे आधुनिक तकनीक, बाजार और वैश्विक अवसरों से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति की नींव रख रही है। यह पहल निश्चित रूप से राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सक्षम होगी। ■



लखनऊ मेट्रो फेज-1बी

विकास की नई रफ्तार, आधुनिक परिवहन की ओर मजबूत कदम

लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सशक्त, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय राजधानी के शहरी ढांचे और यातायात व्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है।

करीब 5801.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाली यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी के साथ क्रियान्वित की जाएगी। यह साझेदारी न केवल संघीय सहयोग का उदाहरण है, बल्कि शहरी विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित यह कॉरिडोर लखनऊ के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को बेहतर ढंग से जोड़कर शहर की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएगा।

लखनऊ मेट्रो फेज-1बी परियोजना प्रदेश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है, जो न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भविष्य की शहरी चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी एक मजबूत आधार तैयार करेगी।

इस परियोजना की डीपीआर को पूर्व में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी थी और भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भी इसे अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अब त्रिपक्षीय एमओयू के माध्यम से इसके क्रियान्वयन की औपचारिक प्रक्रिया को गति मिल गई है। इससे परियोजना के समयबद्ध और प्रभावी निष्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा।

लखनऊ मेट्रो फेज-1बी न केवल यात्रियों को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा, बल्कि शहर में ट्रैफिक दबाव को भी काफी हद तक कम करेगा। इससे प्रदूषण में कमी, समय की बचत और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

यह परियोजना स्मार्ट सिटी की अवधारणा को मजबूत करते हुए लखनऊ को आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद राजधानी के आवागमन पैटर्न में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

कुल मिलाकर, लखनऊ मेट्रो फेज-1बी परियोजना प्रदेश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है, जो न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भविष्य की शहरी चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी एक मजबूत आधार तैयार करेगी। ■



लोहिया संस्थान में 1010 बेडेड अत्याधुनिक इमरजेंसी सेंटर

उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति

लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य संरचना को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की दिशा में अग्रसर है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7, शहीद पथ स्थित संस्थान के नवीन परिसर में 1010 बेड क्षमता वाले अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर, नवीन ओपीडी ब्लॉक तथा 200 सीटों वाले टीचिंग ब्लॉक के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 855 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है, जो प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

यह नया इमरजेंसी सेंटर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जहाँ गंभीर और आपातकालीन मरीजों को त्वरित एवं विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। 1010 बेड की विशाल क्षमता न केवल मरीजों के दबाव को कम करेगी, बल्कि बेहतर प्रबंधन और त्वरित चिकित्सा सेवाओं को भी सुनिश्चित करेगी। इससे राजधानी लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के दूर-दराज़ जिलों से आने वाले मरीजों को भी अत्याधुनिक उपचार का लाभ मिलेगा।

यह पहल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे आम जनता को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

नवीन ओपीडी ब्लॉक के निर्माण से बाह्य रोगी सेवाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे मरीजों की लंबी प्रतीक्षा अवधि में कमी आएगी तथा चिकित्सकों द्वारा अधिक कुशलता से परामर्श और उपचार संभव हो सकेगा। साथ ही, प्रस्तावित टीचिंग ब्लॉक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा, जहाँ 200 सीटों की क्षमता के साथ भावी डॉक्टरों को आधुनिक तकनीक, शोध और व्यवहारिक प्रशिक्षण का बेहतर अवसर मिलेगा।

यह परियोजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगी, बल्कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाएगी। अत्याधुनिक अवसंरचना, प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक के समन्वय से यह केंद्र उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

यह पहल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे आम जनता को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ■

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

विकास की नई उड़ान

निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उभरता केंद्र

उत्तर प्रदेश में तीव्र औद्योगिक एवं शहरी विकास की नई पहचान बन चुका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आज देश के सबसे प्रगतिशील विकास मॉडलों में गिना जा रहा है। सुनियोजित आधारभूत संरचना, तेज प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निवेशकों के अनुकूल वातावरण ने इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है।

यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ प्रारम्भ हुई विकास यात्रा अब औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत विस्तार के रूप में एक नई दिशा प्राप्त कर चुकी है। प्राधिकरण का उद्देश्य केवल भूमि विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक और आत्मनिर्भर शहरी क्षेत्र का निर्माण करना भी है, जहाँ रोजगार, शिक्षा, तकनीक और बेहतर जीवनशैली का समावेश हो।

प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश सरकार का मजबूत प्रशासनिक सहयोग प्राप्त है। सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, पारदर्शी नीतियाँ तथा समयबद्ध सेवाएँ निवेशकों को सरल और भरोसेमंद माहौल प्रदान करती हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, शिक्षा, मेडिकल सुविधाएँ और फिल्म सिटी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश लगातार आकर्षित हो रहे हैं।

यमुना विकास प्राधिकरण की योजनाएँ केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरित क्षेत्र, आधुनिक सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और विश्वस्तरीय शहरी सुविधाएँ इसे भविष्य की स्मार्ट सिटी अवधारणा के अनुरूप बनाती हैं।

विशेष रूप से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना ने इस क्षेत्र की संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक सेक्टरों का एकीकृत विकास इस क्षेत्र को उत्तर भारत का भविष्य का आर्थिक और निवेश हब बना रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उद्योगों को परिवहन, निर्यात और लॉजिस्टिक्स में व्यापक सुविधा मिल रही है।

आज यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण "नए उत्तर प्रदेश" की प्रगतिशील सोच और विकास दृष्टि का सशक्त प्रतीक बन चुका है। यह क्षेत्र न केवल निवेशकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और आधुनिक जीवनशैली के अवसर भी सृजित कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। ■





बीमा और पेंशन क्रांति: विकसित भारत की सुरक्षित और सशक्त नींव

बीमा और पेंशन योजनाएँ विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बनती जा रही हैं। सरकार की सकारात्मक पहल ने करोड़ों लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण तैयार किया है। अब आवश्यकता इन योजनाओं को और अधिक समावेशी, सरल और प्रभावी बनाने की है, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ सके।

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीमा और पेंशन योजनाएँ देश के करोड़ों नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने गरीब, किसान, श्रमिक और मध्यम वर्ग के जीवन में भरोसा और स्थिरता का नया आधार तैयार किया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी पहलें आज देश के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँच चुकी हैं। कम प्रीमियम में बीमा सुविधा मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी सुरक्षा कवच से जुड़ रहा है। डिजिटल बैंकिंग, जनधन खाते और आधार आधारित सेवाओं ने इन योजनाओं की पहुँच को और आसान बनाया है। इससे ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को नई मजबूती मिली है।

अटल पेंशन योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। नियमित अंशदान के माध्यम से बुजुर्गावस्था में निश्चित आय की व्यवस्था होने से लोगों में भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ा है। वहीं बीमा योजनाएँ आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने का कार्य कर रही हैं। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों में सामाजिक सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। जब नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनकी बचत और निवेश की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलती है और विकास को गति प्राप्त होती है। बीमा और पेंशन योजनाएँ केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता का आधार भी बन रही हैं।

हालाँकि इन उपलब्धियों के साथ कुछ सुधारों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। आज भी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक लोग योजनाओं की जानकारी से वंचित हैं। जागरूकता अभियान को पंचायत स्तर तक अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने से अधिक लोगों को जोड़ा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त कई बार दस्तावेज़ीकरण, बैंकिंग प्रक्रियाओं और तकनीकी समस्याओं के कारण पात्र नागरिक योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। आवेदन और दावा प्रक्रिया को और सरल तथा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। महँगाई को देखते हुए बीमा कवरेज और पेंशन राशि में समय-समय पर वृद्धि भी आवश्यक मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीमा और पेंशन योजनाओं को डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय शिक्षा से जोड़ा जाए, तो इनका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। महिलाओं, छोटे किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी उपयोगी सिद्ध होंगे। ■

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड का बड़ा कदम
सतत विकास की नई मिसाल

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक व्यापक एवं दूरदर्शी कार्ययोजना लागू की है। यह पहल केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सतत भविष्य निर्माण का संकल्प भी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु द्वारा सभी विभागों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को जन-आंदोलन का स्वरूप देना है।

सरकार ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों—कोविड महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियाँ, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव—को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया है। सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया गया है तथा अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम न केवल बिजली की बचत करेगा, बल्कि कर्मचारियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करेगा।

ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और साझा वाहन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। "वर्क फ्रॉम होम", "नो व्हीकल डे", वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों और साइकिल शेयरिंग जैसी व्यवस्थाएँ आधुनिक एवं पर्यावरण हितैषी प्रशासनिक संस्कृति को बढ़ावा देंगी।



ऊर्जा संरक्षण एवं सतत विकास की यह व्यापक पहल उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी।

उत्तराखंड सरकार की यह योजना केवल ऊर्जा बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रही है। "Visit My State/Holiday in India" अभियान के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय पर्यटन को गति मिलेगी, लंबी दूरी की अनावश्यक यात्राएँ कम होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

इसी प्रकार "Made in Uttarakhand" अभियान के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और GI टैग उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ODOP, Amazon Karigar और Flipkart Samarth जैसे प्लेटफॉर्मों से MSMEs और स्वयं सहायता समूहों को नई पहचान मिलेगी।

कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और Bio-input आधारित खेती को प्रोत्साहन देकर राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। वहीं सौर ऊर्जा, PNG और CBG परियोजनाओं को बढ़ावा देकर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड नई संभावनाओं की ओर अग्रसर हो रहा है।

ऊर्जा संरक्षण एवं सतत विकास की यह व्यापक पहल उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। ■



उत्तराखंड राज्य के हर विकासखण्ड में उभरेगा समृद्धि का मॉडल गांव

उत्तराखण्ड में कृषि क्रांति की नई पटकथा लिख रही धामी सरकार

उत्तराखण्ड अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक कृषि, जैविक खेती और बागवानी के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों की आय में ऐतिहासिक वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक "आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव" विकसित करने के निर्देश देकर खेती को विकास और समृद्धि के नए मॉडल के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल खेती तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गांवों की संपूर्ण आर्थिक संरचना को मजबूत करने का माध्यम बनेगी। स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के समन्वय से ऐसे गांव विकसित किए जाएंगे जो पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बनें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि

प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, भूमि की गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। इसी आधार पर तय होगा कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल, फल या सब्जी अधिक बेहतर उत्पादन दे सकती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में फलोत्पादन, औषधीय पौधों और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि मैदानी इलाकों में तिलहनी और नकदी फसलों के विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह रणनीति न केवल उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्र विशेष की विशिष्ट पहचान भी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने आगामी तीन वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर योजना के केंद्र में किसान होना चाहिए। खेती की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने और विपणन व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाया जाएगा, ताकि उनकी उपज को बेहतर मूल्य मिल सके और स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के सहयोग से कृषि गोष्ठियां, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीज, आधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक खेती के नए तौर-तरीकों की जानकारी दी जाएगी। "लैब टू लैंड" अभियान के माध्यम से शोध और तकनीकी नवाचारों को सीधे खेतों तक पहुंचाने की भी प्रभावी योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सरसों, तिल, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया।

उनका मानना है कि कृषि विविधीकरण से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित कर उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी ऑर्गेनिक कृषि राज्य बनाने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बायोगैस संयंत्रों तथा सौर ऊर्जा संचालित पंपों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की लागत घटेगी और ऊर्जा के स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल उत्तराखण्ड को हरित विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह योजना केवल कृषि सुधार नहीं, बल्कि ग्रामीण पुनर्जागरण का व्यापक अभियान है। आदर्श कृषि एवं उद्यान गांवों के माध्यम से गांवों में रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर विकसित होंगे। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से धरातल पर उतरती है, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड कृषि, बागवानी और जैविक खेती के क्षेत्र में देश के लिए प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभरेगा। ■

MLC
METAL LASER CRAFT



MLC (Metal Laser Craft)

कला और तकनीक का आधुनिक संगम

MLC (Metal Laser Craft) आज CNC Laser Cutting & Bending के क्षेत्र में गुणवत्ता, सुंदरता और भरोसे का नाम बन चुका है। यह कंपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से क्लाइंट की पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार आकर्षक Interior & Exterior Decor Designs तैयार करती है।

विशेष रूप से लेजर कटिंग से बने जाली डिज़ाइन, गेट, पार्टिशन, वॉल पैनल, सीलिंग डिज़ाइन एवं सजावटी कार्यों में MLC अपनी उत्कृष्ट पहचान रखता है।

- हर डिज़ाइन में नयापन, मजबूती और कलात्मक सुंदरता
- अनुभवी टीम एवं आधुनिक मशीनों द्वारा सटीक कार्य
- अपने ब्राउज़र/डिज़ाइन कैटलॉग उपलब्ध
- यदि आप अपने घर, ऑफिस, शोरूम या किसी भी स्थान को आधुनिक एवं आकर्षक रूप देना चाहते हैं, तो MLC (Metal Laser Craft) आपके सपनों को खूबसूरत वास्तविकता में बदलने के लिए सदैव तत्पर है।
- MLC (Metal Laser Craft) CNC Laser Cutting Bending Interior & Exterior Decor
- "डिज़ाइन जो आपकी पहचान बन जाए"

संपर्क करें!

MD FAKHRUDDIN SAIFI Mob: +919810752137 | **MD SHOAIB** Mob: +919315531995

Plot No: 35, Hindon Enclave, Mahiuddipur Dabrsi, Ghaziabad -201015 (UP)

Near by Jindal Pipe Factory Dasna - Masoori Highway NH - 24

गांव में वैश्विक स्तर तक
भारत की बायोटेक क्रांति



भारत आज जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक) के क्षेत्र में तेज़ी से उभरती वैश्विक शक्ति बन चुका है। यह क्रांति केवल बड़े शहरों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब गांवों तक अपनी मजबूत पहुंच बना चुकी है। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार के क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत बीज, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों ने किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। अब किसान कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और खेती अधिक टिकाऊ बनी है।

डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भी बायोटेक का बड़ा योगदान दिखाई देता है। पशुओं के बेहतर टीके, रोग पहचान तकनीक और पोषण संबंधी अनुसंधानों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। कई गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत की बायोटेक क्रांति ने दुनिया को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। गांवों तक टीकाकरण अभियान पहुंचाकर भारत ने यह साबित किया कि विज्ञान और समाज का मेल विकास की सबसे बड़ी ताकत है। आज भारतीय बायोटेक कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।

भारत की बायोटेक क्रांति गांवों से शुरू होकर वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है, जो आने वाले वर्षों में देश की प्रगति का मजबूत आधार सिद्ध होगी।

सरकार की "बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC)" और "स्टार्टअप इंडिया" जैसी योजनाओं ने युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित किया है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले युवा अब बायोटेक स्टार्टअप स्थापित कर रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

भारत की बायोटेक क्रांति का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि यह विकास को गांव से जोड़ रही है। विज्ञान अब केवल प्रयोगशालाओं की सीमाओं में नहीं, बल्कि खेतों, पशुपालन केंद्रों और ग्रामीण उद्यमों में दिखाई दे रहा है। यही परिवर्तन भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

भारत की बायोटेक क्रांति गांवों से शुरू होकर वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है, जो आने वाले वर्षों में देश की प्रगति का मजबूत आधार सिद्ध होगी। ■

पीएमईजीपी योजना
सूक्ष्म उद्यमों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव

PMEGP योजना देश में सूक्ष्म उद्यमों की नई क्रांति लेकर आई है। रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर यह योजना भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।



भारत में रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंत्रालय के अनुसार इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 3.6 मिलियन (36 लाख) से अधिक रोजगार अवसर सृजित किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा परिवर्तन है।

PMEGP योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करना आसान हो जाता है। खादी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में हजारों सूक्ष्म उद्यम स्थापित हुए हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल रोजगार खोजने की मानसिकता को बदलकर रोजगार देने वाले उद्यमी तैयार कर रही है। गांवों और छोटे शहरों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग विकसित होने से पलायन में कमी आई है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत है।

डिजिटल प्रक्रिया, बैंकिंग सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने भी योजना को अधिक प्रभावी बनाया है। आज अनेक युवा स्टार्टअप और पारंपरिक व्यवसायों के आधुनिक रूप विकसित कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दे रहे हैं।

स्पष्ट है कि PMEGP योजना देश में सूक्ष्म उद्यमों की नई क्रांति लेकर आई है। रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर यह योजना भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ■



भारत: उभरते बाजारों का अडिग सितारा, वैश्विक झटकों के बीच विकास का भरोसेमंद चेहरा

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और व्यापारिक अस्थिरता ने कई देशों की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित किया है। ऐसे समय में भारत ने अपनी मजबूत आर्थिक नीतियों, विशाल घरेलू बाजार और स्थिर विकास दर के दम पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी Moody's ने भारत को "सबसे मजबूत उभरता बाजार" बताते हुए कहा है कि देश आर्थिक झटकों को संभालने की उल्लेखनीय क्षमता रखता है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत घरेलू मांग और युवा जनसंख्या है। तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल क्रांति और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था देश को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। वैश्विक मंदी के दबाव के बावजूद भारत में निवेश का माहौल सकारात्मक बना हुआ है। विदेशी निवेशकों का भरोसा इस बात का प्रमाण है कि भारत भविष्य की आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आज भारत दुनिया के लिए केवल एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिरता, नवाचार और भरोसे का प्रतीक बनकर उभर रहा है।

सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने भी आर्थिक मजबूती को नई ऊर्जा दी है। "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश ने उद्योग, रोजगार और नवाचार को गति दी है। विनिर्माण क्षेत्र में तेजी और तकनीकी विकास ने भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूपीआई की सफलता और वित्तीय समावेशन ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और कृषि क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी भागीदारी भी विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल एशिया ही नहीं, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बन सकता है। आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत का संतुलित प्रदर्शन यह साबित करता है कि देश न केवल संकटों का सामना करने में सक्षम है, बल्कि अवसरों को विकास में बदलने की अद्भुत क्षमता भी रखता है।

आज भारत दुनिया के लिए केवल एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिरता, नवाचार और भरोसे का प्रतीक बनकर उभर रहा है। ■



"स्मार्ट खर्च से मजबूत भारत": प्रधानमंत्री मोदी की अपील में छिपा आर्थिक आत्मविश्वास

देश की अर्थव्यवस्था केवल सरकारों की नीतियों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों की आर्थिक आदतों से भी मजबूत होती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से खर्च रोकने की नहीं, बल्कि "समझदारी से खर्च करने" की अपील कर रहे हैं। यह संदेश केवल बचत का नहीं, बल्कि संतुलित और जिम्मेदार आर्थिक व्यवहार का प्रतीक बनता जा रहा है।

आज का दौर उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था का है, जहाँ हर व्यक्ति का खर्च बाजार, उद्योग और रोजगार को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य लोगों को डराकर खर्च कम करवाना नहीं, बल्कि उन्हें प्राथमिकताओं के अनुसार सोच-समझकर खर्च करने के लिए प्रेरित करना है। यानी अनावश्यक दिखावे और फिजूलखर्ची से बचते हुए ऐसी खरीदारी को बढ़ावा देना, जिससे परिवार भी सुरक्षित रहे और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो।

प्रधानमंत्री की "वोकल फॉर लोकल" सोच भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब नागरिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो छोटे उद्योग, कारीगर और स्टार्टअप्स को नई ऊर्जा मिलती है। इससे रोजगार बढ़ता है और देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता है। समझदारी से किया गया खर्च सीधे तौर पर देश के विकास चक्र को गति देता है।

प्रधानमंत्री की "वोकल फॉर लोकल" सोच भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब नागरिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो छोटे उद्योग, कारीगर और स्टार्टअप्स को नई ऊर्जा मिलती है। इससे रोजगार बढ़ता है और देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता है।

इसके साथ ही डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बजटिंग और वित्तीय जागरूकता जैसे विषयों पर सरकार का जोर भी नागरिकों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बना रहा है। आज का युवा वर्ग निवेश, बीमा और बचत के महत्व को समझ रहा है। यह बदलाव भारत को केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से जिम्मेदार समाज बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

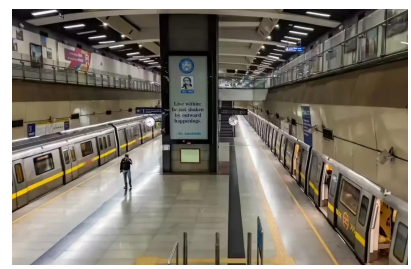
प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है — "खर्च कीजिए, लेकिन सोच-समझकर।" यह अपील नकारात्मक प्रतिबंध नहीं, बल्कि सकारात्मक आर्थिक अनुशासन की प्रेरणा है। यदि देश का हर नागरिक संतुलित खर्च, स्थानीय उत्पादों के समर्थन और वित्तीय जिम्मेदारी को अपनाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त बन सकती है। यही स्मार्ट खर्च भविष्य के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव है। ■



आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार बनी दिल्ली मेट्रो अब नए कॉरिडोर में दिखेगी 'मेड-इन-इंडिया' तकनीक की चमक

देश की राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का प्रतीक बन चुकी Delhi Metro Rail Corporation अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊँचाई देने जा रही है। दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर में पहली बार पूरी तरह "मेड-इन-इंडिया" प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे। यह कदम केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमता और स्वदेशी नवाचार का भी मजबूत प्रमाण है।

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (PSD) वे स्वचालित दरवाजे होते हैं जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इनके लगने से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ती है, दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है तथा ऊर्जा संरक्षण में



भी मदद मिलती है। अब तक ऐसी तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता अधिक थी, लेकिन दिल्ली मेट्रो का यह निर्णय भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएगा।

इस पहल का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे देश के विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी। स्वदेशी कंपनियों को बड़े स्तर पर उत्पादन का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिलेगा। यह कदम "लोकल फॉर वोकल" की भावना को भी मजबूत करता है।

निश्चित रूप से दिल्ली मेट्रो की यह पहल केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि जब भारतीय नवाचार और संकल्प साथ आते हैं, तब देश विकास की नई पटरी पर तेजी से आगे बढ़ता है।

दिल्ली मेट्रो पहले से ही आधुनिक परिवहन व्यवस्था, समयबद्ध संचालन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती है। अब स्वदेशी तकनीक को अपनाकर उसने यह संदेश दिया है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय तकनीक विकसित करने वाला देश भी बन रहा है। इससे अन्य सरकारी और निजी परियोजनाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे भारतीय उत्पादों और तकनीकों को प्राथमिकता दें।

विशेषज्ञों का मानना है कि मेड-इन-इंडिया प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लागत को कम करने के साथ-साथ रखरखाव को भी आसान बनाएंगे। भविष्य में यदि इन तकनीकों का निर्यात शुरू होता है, तो भारत वैश्विक मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

निश्चित रूप से दिल्ली मेट्रो की यह पहल केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि जब भारतीय नवाचार और संकल्प साथ आते हैं, तब देश विकास की नई पटरी पर तेजी से आगे बढ़ता है। ■

डिजिटल क्रांति से बदली छोटे कारोबारों की तस्वीर



भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल पहुंच ने छोटे कारोबारों के लिए विकास के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान सेवाओं के विस्तार ने अब गांवों और छोटे शहरों के व्यापारियों को भी बड़े बाजार से जोड़ दिया है। यही कारण है कि छोटे कारोबार आज केवल स्थानीय ग्राहकों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं।

डिजिटल इंडिया अभियान और सस्ती इंटरनेट सेवाओं ने व्यापार करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां छोटे दुकानदार केवल नकद लेन-देन पर निर्भर रहते थे, वहीं अब यूपीआई, क्यूआर कोड और मोबाइल बैंकिंग ने भुगतान को आसान और सुरक्षित बना दिया है। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है और कारोबारियों की आय में भी वृद्धि हुई है।

सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म छोटे उद्यमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। घर से संचालित होने वाले छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, कपड़ा, खाद्य सामग्री और स्थानीय उत्पाद अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए

हजारों ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। इससे महिलाओं और युवाओं को भी स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।

डिजिटल पहुंच केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। यह परिवर्तन छोटे कारोबारों को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। आने वाले समय में डिजिटल विकास छोटे उद्यमों की सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

डिजिटल पहुंच का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह है कि छोटे कारोबार अब कम लागत में अधिक प्रचार कर पा रहे हैं। पहले विज्ञापन के लिए भारी खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए व्यापारी अपने उत्पादों की जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन ग्राहक सेवा और डिजिटल मार्केटिंग ने प्रतिस्पर्धा में उन्हें मजबूत बनाया है।

सरकार द्वारा डिजिटल प्रशिक्षण, मुद्रा योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन जैसी पहलें भी छोटे व्यापारियों को नई ऊर्जा दे रही हैं। कई ग्रामीण उद्यमी अब तकनीक का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है।

डिजिटल पहुंच केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। यह परिवर्तन छोटे कारोबारों को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। आने वाले समय में डिजिटल विकास छोटे उद्यमों की सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। ■

रिकॉर्ड पैदावार से खुला निर्यात का रास्ता

चार साल बाद फिर चमका भारत का गेहूं बाजार



चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक बार फिर गेहूं निर्यात शुरू कर वैश्विक कृषि बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह केवल व्यापारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय किसानों की मेहनत, बेहतर कृषि नीतियों और अनुकूल मौसम का संयुक्त परिणाम है। इस वर्ष देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जिसने घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखते हुए निर्यात के नए अवसर पैदा किए हैं।

भारत विश्व के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक परिस्थितियों, घरेलू महंगाई और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं निर्यात पर नियंत्रण लगाया था। लेकिन इस बार भरपूर पैदावार ने स्थिति बदल दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गेहूं उत्पादन ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे भंडारण क्षमता मजबूत हुई और किसानों को बेहतर बाजार मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

चर साल बाद गेहूं निर्यात की वापसी भारत की कृषि शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि यदि सही नीतियां, तकनीक और किसानों का परिश्रम साथ आएं, तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

निर्यात शुरू होने का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव किसानों की आय पर दिखाई देगा। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ेगी, तब किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना भी बनेगी। साथ ही भारत की खाद्यान्न आपूर्ति क्षमता पर दुनिया का भरोसा और मजबूत होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का गेहूं गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमत के कारण कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व के देशों में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है। इससे विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि होगी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

यह उपलब्धि आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और किसानों की जागरूकता का भी परिणाम है। सरकार द्वारा सिंचाई, उर्वरक और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चार साल बाद गेहूं निर्यात की वापसी भारत की कृषि शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि यदि सही नीतियां, तकनीक और किसानों का परिश्रम साथ आएं, तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ■



नए लेबर कोड: श्रमिक सुरक्षा और आर्थिक विकास की नई उड़ान"

भारत में श्रम सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड लागू करने की प्रक्रिया को गति दी है। नियमों की अधिसूचना के साथ ही ये श्रम संहिताएँ देश की कार्य संस्कृति, श्रमिक सुरक्षा और औद्योगिक विकास में व्यापक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। लंबे समय से अलग-अलग कानूनों में बंटी श्रम व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से इन चार लेबर कोड—वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल परिस्थितियाँ संहिता—को तैयार किया गया है।

इन नए श्रम कानूनों का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि इससे श्रमिकों और उद्योगों दोनों के हितों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। पहले श्रम कानूनों की जटिलता के कारण उद्योगों को अनेक प्रक्रियाओं और अनुमतियों से गुजरना पड़ता था। अब कानूनों के सरलीकरण से उद्योगों को कार्य करने में सुविधा मिलेगी, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलने से भारत वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है।

वेतन संहिता के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया गया है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सुरक्षा मिलेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलने से श्रमिकों में विश्वास और कार्यक्षमता बढ़ेगी।

सामाजिक सुरक्षा संहिता का दायरा बढ़ाकर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यह डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के दौर में एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। अब ऑनलाइन सेवा क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मचारियों को भी पेंशन, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इससे श्रमिकों के भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक संबंध संहिता उद्योगों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद तथा विवादों के त्वरित समाधान पर बल देती है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक वातावरण अधिक सकारात्मक बनेगा। वहीं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा।

इन सुधारों का एक अन्य सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में देखा जा रहा है। सरल नियमों और डिजिटल प्रक्रियाओं से छोटे एवं मध्यम उद्योगों को विस्तार में सहायता मिलेगी। जब उद्योगों को संचालन में आसानी होगी, तब नए रोजगार अवसर भी तेजी से उत्पन्न होंगे। इससे युवाओं को लाभ मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।

हालाँकि इन कानूनों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाना, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक होगा। यदि सरकार, उद्योग और श्रमिक संगठन मिलकर सहयोग करें, तो ये श्रम सुधार भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

चार नए लेबर कोड केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हैं। ये सुधार श्रमिकों को सुरक्षा, उद्योगों को सुविधा और देश को विकास की नई गति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ■

“श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश”

योगी सरकार की नई योजनाओं से रोजगार, कौशल और सुरक्षा को मिलेगा विस्तार



उत्तर प्रदेश में श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों के कल्याण को केंद्र में रखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार अब श्रमिकों को केवल कार्यबल नहीं, बल्कि राज्य की प्रगति और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने “बाल श्रमिक विद्या योजना” को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2020 में शुरू हुई यह योजना अब तक 20 जिलों में संचालित थी, जिसके तहत आर्थिक मजबूरी में काम करने वाले बच्चों को विद्यालयों से जोड़कर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।

रोजगार और जनसुविधा को तकनीक से जोड़ने वाली “सेवामित्र व्यवस्था” को भी और मजबूत किया जाएगा। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित इस प्रणाली के माध्यम से नागरिक घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में हजारों सेवामित्र और कुशल कामगार इससे जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भी आवश्यकता अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए इसे पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बताया।

निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े औद्योगिक शहरों में आधुनिक “श्रमिक सुविधा केंद्र” विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों में श्रमिकों के लिए सुरक्षित आवास, सहायता सेवाएं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना को भी कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, फिटर और अन्य तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रदेश में रोजगार सृजन को गति देने के लिए सरकार “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन” के माध्यम से युवाओं को देश और विदेश में अवसर उपलब्ध करा रही है। जर्मनी, जापान और अन्य देशों में रोजगार संभावनाओं के अनुरूप भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सेवायोजन विभाग को आधुनिक डिजिटल रोजगार तंत्र के रूप में विकसित करने तथा एआई आधारित जॉब मैचिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं।

योगी सरकार की ये पहलें स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश अब श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और आधुनिक रोजगार व्यवस्था के जरिए आत्मनिर्भर और सशक्त समाज की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ■



उड़ान को नई रफ़्तार

दिल्ली-जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर से बदलेगी NCR की तस्वीर

दिल्ली-NCR को मिलेगा ट्रैफिक से राहत का नया रास्ता

दिल्ली-NCR में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और लंबी यात्रा से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा विकसित किया जा रहा **DND–फरीदाबाद–सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे और जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर** क्षेत्र की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने जा रहा है। लगभग 59 किलोमीटर लंबा यह छह-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना को सीधे आगामी **नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से** जोड़ेगा।

करीब 4,463 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा समय कम करेगा, बल्कि दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को भी काफी हद तक घटाने में मदद करेगा।

दक्षिण दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक आसान सफर

वर्तमान में दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को नोएडा होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन इस नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद यात्रियों को सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। खासकर NH-44 और धौला कुआं जैसे व्यस्त मार्गों पर वाहनों की संख्या घटने की उम्मीद है।

दिल्ली डिकंजेशन प्लान का अहम हिस्सा

यह परियोजना केंद्र सरकार की लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की "दिल्ली डिकंजेशन योजना" का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत NCR में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है, जिनमें शामिल हैं—

- दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे विस्तार
- अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II)
- द्वारका एक्सप्रेसवे टनल
- AIIMS-महिपालपुर एलिवेटेड कॉरिडोर
- कालिंदी कुंज इंटरचेंज

इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक, प्रदूषण और यात्रा समय को कम करना है।

आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण

इस कॉरिडोर की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है **आगरा नहर पर बन रहा 140 मीटर लंबा नेटवर्क आर्च ब्रिज**। इसे दिल्ली-NCR का पहला आधुनिक नेटवर्क आर्च ब्रिज बताया जा रहा है।

इस पुल की प्रमुख विशेषताएँ

- बीच में कोई पिलर नहीं, जिससे नहर का प्रवाह बाधित नहीं होगा
- अत्याधुनिक स्टील आर्च तकनीक
- भूकंपरोधी संरचना
- हाई-डैम्पिंग रबर बेयरिंग और स्विवल एक्सपेंशन जॉइंट्स
- लगभग 2,396 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग

यह पुल आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीकी दक्षता का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान

परियोजना में पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। निर्माण कार्य में ओखला और गाज़ीपुर लैंडफिल से प्राप्त लगभग 2 लाख मीट्रिक टन बायो-माइनिंग सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे प्राकृतिक मिट्टी पर निर्भरता कम हुई है।

इसके अलावा परियोजना में

- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण
- नॉइज़ बैरियर
- आकर्षक लैंडस्केपिंग

जैसी पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्थाएँ भी शामिल की गई हैं।

NCR के विकास को मिलेगा नया आयाम

विशेषज्ञों के अनुसार यह कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि NCR की आर्थिक और लॉजिस्टिक प्रगति का नया आधार बनेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना दिल्ली-NCR के लोगों के लिए तेज़, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का प्रतीक बन सकती है। ■



श्रीअन्न की ओर लौटता भारत

स्वस्थ जीवनशैली में मिलेट्स बने नई पहचान

पारंपरिक अनाजों की बढ़ती लोकप्रियता

कभी केवल ग्रामीण क्षेत्रों या विशेष मौसम में उपयोग किए जाने वाले मोटे अनाज आज भारतीय परिवारों की थाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और जौ जैसे मिलेट्स अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली का प्रतीक बन चुके हैं। हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार देश के लगभग 70 प्रतिशत परिवार नियमित रूप से किसी न किसी रूप में मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं।

स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी जागरूकता

कोविड महामारी के बाद लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ी है। लोग अब केवल स्वाद नहीं, बल्कि पौष्टिकता को भी महत्व देने लगे हैं। सर्वे में लगभग 43 प्रतिशत लोगों ने माना कि वे स्वास्थ्य लाभ के कारण मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। वहीं 30 प्रतिशत लोगों ने भोजन में विविधता लाने के लिए और 15 प्रतिशत लोगों ने धार्मिक उपवास के कारण इनका सेवन बढ़ाया है।

मिलेट्स फाइबर, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाने, वजन नियंत्रित रखने तथा मधुमेह जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक माने जाते हैं।

हल्के और पौष्टिक स्नैक्स की बढ़ती मांग

आजकल लोग शाम के नाश्ते में भी स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुन रहे हैं। मखाना, भुना चना, मुरमुरा, भेल और मूंगफली जैसे पारंपरिक स्नैक्स की मांग लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक संगठनों के अनुसार कोविड के बाद लोगों ने तली-भुनी चीजों की जगह हल्के और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना शुरू किया है।

सरकारी योजनाओं में शामिल करने की मांग

सर्वे में 68 प्रतिशत परिवारों ने यह मांग की कि मोटे अनाजों को सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में चावल और गेहूं की तरह शामिल किया जाए। लोगों का मानना है कि यदि मिलेट्स आम जनता तक सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे, तो देश में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

'श्रीअन्न' अभियान का असर

पिछले कुछ वर्षों में देश में 'श्रीअन्न' को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा भी नागरिकों से दैनिक आहार में मिलेट्स शामिल करने की अपील की गई थी। इसका सकारात्मक प्रभाव अब बाजार और लोगों की खानपान की आदतों में साफ दिखाई दे रहा है।

मिलेट्स का बढ़ता उपयोग केवल खानपान का बदलाव नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली की ओर बढ़ता कदम है। भारत अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति की ओर लौट रहा है, जहाँ स्वाद के साथ स्वास्थ्य को भी समान महत्व दिया जा रहा है। आने वाले समय में 'श्रीअन्न' भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा बनकर देश को स्वस्थ और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ■



संघे शक्ति कलियुगे

विकेन्द्रित उत्पादन से आत्मनिर्भर बनती ग्रामीण महिलाएं

झारखंड की गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच X पर साझा किए गए अपने विचारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म दिया है। उन्होंने "संघे शक्ति कलियुगे" की अवधारणा को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध "श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़" मॉडल को महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

महिला एवं बाल विकास समिति, झारखंड विधानसभा की सभापति के रूप में महाराष्ट्र एक्सपोज़र विजिट के दौरान उन्हें मुंबई स्थित डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर का अवलोकन करने का अवसर मिला। लगभग 135 वर्षों से अनुशासन, समयबद्धता और उत्कृष्ट सेवा के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध मुंबई डब्बावालों की कार्यशैली ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। यह अनुभव केवल प्रबंधन का उदाहरण नहीं था, बल्कि सामूहिक श्रम, विश्वास और समर्पण की शक्ति का भी परिचायक बना।

अपने संदेश में उन्होंने विशेष रूप से "लिज्जत पापड़" के सहकारी मॉडल की सराहना की। उनके अनुसार यह केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का ऐसा आंदोलन है जिसने लाखों महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भरता से जोड़ा। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता "विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली" है, जिसमें महिलाएं घर या स्थानीय स्तर पर रहकर उत्पादन कार्य कर सकती हैं। इससे वे परिवार और रोजगार दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं।

विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। भारत के गांवों में पारंपरिक कौशल, स्थानीय संसाधन और श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्हें सही दिशा और प्रशिक्षण देकर बड़े आर्थिक परिवर्तन में बदला जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि लिज्जत पापड़ जैसे सफल सहकारी मॉडल को हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हथकरघा और अन्य लघु उद्योगों में भी लागू किया जाना चाहिए।

"संघे शक्ति कलियुगे" की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। सामूहिक प्रयास, सहयोग और आत्मविश्वास के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत और सशक्त ग्रामीण समाज का निर्माण संभव है।

आज के समय में जब ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन एक बड़ी चुनौती बन चुका है, ऐसे विकेन्द्रित उत्पादन मॉडल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी में भी वृद्धि होगी।

श्रीमती कल्पना सोरेन ने सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया है, ताकि ग्रामीण परिवारों को स्थायी और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराई जा सके। उनका यह संदेश केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक सोच का प्रतीक बनकर उभरा है। ■



वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत

क्यों अहम हैं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे

पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों ने भारत की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई दी है। ये यात्राएं केवल औपचारिक कूटनीतिक मुलाकातें नहीं हैं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक शक्ति को दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत करने का माध्यम बन चुकी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और कई अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा दी है। इन दौरों का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह रहा कि भारत को वैश्विक निवेश का भरोसेमंद केंद्र माना जाने लगा है। विदेशी कंपनियों ने "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसी योजनाओं में रुचि दिखाई, जिससे रोजगार और तकनीकी विकास को गति मिली।

विदेश नीति के स्तर पर भी भारत की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत ने संतुलित और स्वतंत्र नीति अपनाकर विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। जी-20 की सफल अध्यक्षता ने यह साबित किया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नए भारत की वैश्विक सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। इन यात्राओं ने भारत को विश्व मंच पर अधिक प्रभावशाली, सक्षम और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन यात्राओं का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव भी है। जहां भी प्रधानमंत्री मोदी गए, वहां भारतीय समुदाय ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इससे दुनियाभर में बसे भारतीयों का मनोबल बढ़ा और भारत की सांस्कृतिक छवि मजबूत हुई। योग, आयुर्वेद और भारतीय परंपराओं को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली।

सुरक्षा और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी इन दौरों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कई देशों के साथ रक्षा समझौते हुए, आधुनिक तकनीक का आदान-प्रदान बढ़ा और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति को मजबूती मिली।

प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नए भारत की वैश्विक सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। इन यात्राओं ने भारत को विश्व मंच पर अधिक प्रभावशाली, सक्षम और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ■

IFFCO KISAN DRONE

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

इफको नैनो उर्वरक अपनाएं
अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं
इफको की असरदार जोड़ी

नैनो यूरिया प्लस

नैनो डीएपी



नैनो जिंक

नैनो कॉपर

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967

www.iffco.in | www.nanourea.in I www.nanodap.in

आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के



सभी वरिष्ठ नागरिकों

को मिल रहा वय वंदना योजना का लाभ



योजना की विशेषताएं

- सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार
- मौजूदा बीमारियों का कवरेज पहले दिन से लागू
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, जिनके पास पहले से कोई निजी बीमा है, वे भी पात्र होंगे
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य बीमा योजना (ESIC) के लाभार्थी भी पात्र होंगे

कैसे बनवाएं आयुष्मान वय वंदना कार्ड?

प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें → मोबाइल नंबर से लॉगिन करें → सभी आवश्यक जानकारी भरें और e-KYC करें → अपना कार्ड डाउनलोड करें

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर

पात्रता के मापदंड

लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है

आयु का सत्यापन आधार e-KYC के माध्यम से ही पूरा होगा



आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत

15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष अभियान

इस दौरान अपने नजदीकी कैंप पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए QR कोड स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 1800-1800-4444/14555

कार्यालय का पता — दूसरी और चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

अब इंतजार किस बात का,
आज ही ऐप डाउनलोड कर बनवाएं

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश · UPGovtOfficial · CMOUttarpradesh · CMOfficeUP